

प्रेषक,

राकेश शर्मा,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7

देहरादून: दिनांक 09 <sup>अक्टूबर</sup> जून, 2015

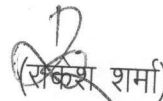
विषय:- शासकीय फील्ड कार्मिकों को स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) के स्थान पर वाहन भत्ता अनुमन्य किया जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-745/xxvii(7)27(20)/2013 दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 एवं शासनादेश संख्या-779/xxvii(7) 27 (20)/2013 T.C. दिनांक 12.11.2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन विभागों में फील्ड कर्मचारी निजी वाहन से शासकीय कार्यों का सम्पादन करते हैं, उन विभागों के विभागाध्यक्ष के स्थान पर आहरण-वितरण अधिकारी और यदि वह स्वयं आहरण वितरण अधिकारी हो तो उनसे उच्च अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा कि सम्बन्धित कर्मिक द्वारा शासकीय कार्यों में निजी वाहन का प्रयोग किया जा रहा है, तदोपरान्त ही उन्हें वाहन भत्ता अनुमन्य होगा।

2. उपर्युक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 12 नवम्बर, 2013 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

  
(राकेश शर्मा)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या: १६ (१) / xxvii(7)27(20) / 2009 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. सचिव विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून ।
3. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल ।
5. स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
- ✓ 6. निदेशक, एन०आई०सी० उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
7. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,



(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)

अपर सचिव ।